



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2019/श्रावण 30, 1941
No. 295] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2019/SHRAVANA 30, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 6 अगस्त, 2019

सं. टीएमपी/14/2019-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तंगहाल पीपीपी परियोजनाओं पर पोत परिवहन मंत्रालय के 11 जुलाई, 2018 के पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी-कक्ष के अनुपालन में, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा इस प्राधिकरण के 2 जनवरी, 2015 के आदेश संख्या टीएमपी/36/2014-वीपीटी के द्वारा अदानी विजाग कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के लिए वीपीटी में डीबीओएफटी आधार पर भीतरी हार्बर की ईस्ट-1 बर्थ पर वाष्प कोयले के मशीनीकृत प्रहस्तन के लिए अदानी विजाग कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अधिसूचित दरमानों में निशुल्क अवधि में वृद्धि और भंडारण अनुसूची में संशोधन के संबंध में विशाखापट्टणम पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/14/2019-वीपीटी

विशाखापट्टणम पत्तन न्यास

आवेदक

गणपूर्ति

- (i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जुलाई 2019 के 24वें दिन पारित)

यहां मामला इस प्राधिकरण के 2 जनवरी, 2015 के आदेश संख्या टीएमपी/36/2014-वीपीटी के द्वारा अदानी विजाग कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के लिए वीपीटी में डीबीओएफटी आधार पर भीतरी हार्बर की ईस्ट-1 बर्थ पर वाष्प कोयले के मशीनीकृत प्रहस्तन के लिए अदानी विजाग कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अधिसूचित दरमानों में निशुल्क अवधि में वृद्धि और भंडारण अनुसूची में संशोधन के संबंध में विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) के 12 फरवरी, 2019 के प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. वीपीटी के प्रस्ताव में उठाये गए मुख्य मुद्दों का सारांश नीचे दिया जाता है:-

- (i) परियोजना वीपीटी पर डीबीएफओटी आधार पर 8.8.2012 को 6.41 एमटीपीए क्षमता के साथ एवीसीटीपीएल को अवार्ड की गई थी। परियोजना 2.9.2014 को पूरी हुई 24.10.2014 को प्रचालन आरंभ हुआ।
- (ii) एवीसीटीपीएल द्वारा यह अभ्यावेदन दिया गया है कि आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन के कारण वाष्प कोयले के आयात में कमी होना, पैनामैक्स से केप पोतों की मात्रा में अंशांकन होने और उच्च भंडारण प्रभावों जैसे विभिन्न कारणों से सुविधा का उपयोग औसत से कम हो रहा है। ग्राही ने निम्नलिखित निवेदन भी किया है:-

“विशाखापट्टणम पत्तन स्थित बर्थ ईक्वू-1 का प्रचालन अत्यंत कठिन और असंभव हो गया है और इस स्थिति में सुधार की भी कोई गुंजाइश नहीं है।”

- (iii) महापत्तनों में पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में उठाये जाते रहे हैं। मुद्दे के महत्व को देखते हुए पोत परिवहन मंत्रालय ने कोई निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष आईपीए की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पोत परिवहन मंत्रालय के 11 जुलाई, 2018 के पत्र संख्या पीडी- 13/1/2018-पीपीपी के द्वारा सभी महापत्तनों और इस प्राधिकरण भेजी गई थी और यह निदेश दिया था कि सृजित सुविधा के इष्टतम उपयोग के लिए स्थिति की सांवाधिक समीक्षा सहित रिपोर्ट में अंतर्विष्ट प्रक्रिया को अपनाया जाये।

- (iv) मंत्रालय के निदेशों को एवीसीटीपीएल को अभियुक्ति के लिए भेजा गया था। प्रत्युत्तर में एवीसीटीपीएल ने अपने 27 अगस्त, 2018 के पत्र के द्वारा समिति की रिपोर्ट के अनुसार “तंगहाल परियोजना” के वर्गीकरण के मानदंडों के अनुरूप तत्संबंधी आंकड़े भी प्रस्तुत किये। एवीसीटीपीएल ने एवीसीटीपीएल को तंगहाल आस्ति घोषित करने, स्टॉकयार्ड में 5 दिन की कार्गो भंडारण की निशुल्क अवधि के प्रति सुपरमैक्स/हैंडीमैक्स पोतों के लिए 40 निशुल्क दिवस पर सुविचार करने और पैनामैक्स पोत के 45 दिन की निशुल्क अवधि पर सुविचार करने का अनुरोध किया।

(क) 27 अगस्त, 2018 के अपने पत्र में एवीसीटीपीएल द्वारा उठाये गए मुख्य बिंदु निम्नवत् हैं:-

- (i) वीपीटी को समय-समय पर लिखे विभिन्न पक्षों में दिये गए विभिन्न कारणों से एवीसीटीपीएल परियोजना की क्षमता के अनुरूप कार्गो का प्रहस्तन नहीं कर सका है।

पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रहस्तित कार्गो का ब्यौरा नीचे दिया जाता है:

वित्त वर्ष	प्रहस्त कार्गो (एमएमटी में)	अभियुक्ति
2014-15	0.97	वीपीटी के यातायात विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत है।
2015-16	0.88	वीपीटी के यातायात विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत है।
2016-17	शून्य	वीपीटी के यातायात विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत है।
2017-18	शून्य	वीपीटी के यातायात विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत है।

पिछले 4 वित्त वर्षों में प्रहस्तित कार्गो - 1.85 एमएमटी है।

- (ii) एवीसीटीपीएल अपने प्रचालन के आरंभ से ही काफी घाटे में चल रहा है। पिछले 2 वित्त वर्षों, यानी 2016-17 और 2017-18, के दौरान एवीसीटीपीएल द्वारा बहन की गई नकद हानि का ब्यौरा, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत् प्रभाजित, प्रस्तुत है।
- (iii) ग्राहकों को एवीसीटीपीएल की ओर आकर्षित करने में अत्यधिक भंडारण प्रभार एक बाधा है। प्रतिस्पर्धी पत्तन सस्ते विकल्प हैं। आस-पास के सभी प्रतिस्पर्धी पत्तन 45-60 दिन की निशुल्क भंडारण अवधि दे रहे हैं।
- (iv) उक्त को देखते हुए, एवीसीटीपीएल ने अपने टर्मिनल में कार्गो भंडारण के लिए निम्नलिखित निशुल्क दिवसों का प्रस्ताव वीपीटी से किया है:

क्र.सं.	पोत आकार	प्रस्तावित निशुल्क दिवस
1	सुपरमैक्स/हैंडीमैक्स	40
2	पैनामैक्स	45

उक्त को देखते हुए, एवीसीटीपीएल ने वीपीटी को अनुरोध किया है कि वे अपनी परियोजना को तंगहाल परियोजना समझें और पोत परिवहन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरोध निशुल्क भंडारण दिवसों का प्रस्ताव प्राधिकरण को अग्रेषित करें।

2.2. हमारे 20 फरवरी, 2019 के पत्र के उत्तर में, वीपीटी ने अपने 28 मार्च, 2019 के पत्र के द्वारा बताया है कि सिद्धांत रूप में अनुमोदित एवीसीटीपीएल की संशोधित भंडारण अनुसूची का कार्यान्वयन 20 फरवरी 2019 से प्रभावी हुआ है और निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है:-

- (i) वर्ष 2014-15 से 2017-18 में एवीसीटीपीएल द्वारा प्रहस्तित वास्तविक यातायात इस प्रकार है:-

वर्ष	प्रहस्तित कार्गो (एमएमटी में)
2014-15	1.01
2015-16	0.85
2016-17	शून्य
2017-18	शून्य

- (ii) एवीसीटीपीएल के 4 जनवरी, 2019 के पत्र की एक प्रति, जिसमें उसके लेखापरीक्षकों से चार्टरित लेखाकारों का प्रमाणपत्र भेजा गया है कि पिछले 2 वित्त वर्षों का एवीसीटीपीएल का नकद धारा और नेट-वर्थ नीचे सारणीबद्ध की जाती है:-

(लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	वि.वर्ष 2016-17	वि.वर्ष 2017-18
	लाभ हानि विवरण के अनुसार निवल हानि	(4,020.51)	(18,528.60)
	जमा- मूल्यह्रास	2,258.21	1,676.81
	जमा – आपवादिक मदें (हानिकरण प्रावधान)	-	15,518.00
1.	कंपनी द्वारा बहन की गई नकद हानि	(1,762.30)	(1,333.79)
2.	कंपनी की नेट-वर्थ	(1855.84)	(20384.44)

उक्त नकद हानि और नेट-वर्थ इन दो वर्षों के दौरान अपनी होलिंग कंपनी से लिये गए उधार पर ब्याज के बाजदावे के प्रभाव को छोड़ दिया गया है।

3.1. वीपीटी ने एवीसीटीपीएल के अनुरोध को वीपीटी के न्यासी मंडल की 16.11.2018 को हुई बैठक में समीक्षा और चर्चा के लिए रखा था। विस्तार से चर्चा और समीक्षा करने के पश्चात्, वीपीटी के न्यासी मंडल की यह राय थी कि ग्राही मैसर्ज एवीसीटीपीएल का उक्त परियोजना को “तंगहाल परियोजना” के रूप वर्गीकरण करने के प्रस्ताव पर सुविचार किया और निम्नलिखित संकल्प किया, बशर्ते ग्राही बोर्ड के निदेशानुसार अकरण की घटनाओं को दूरे करेगा और तत्पश्चात् इस प्राधिकरण द्वारा परामर्शी सूचना की सशर्त वापसी की जायेगी। वीपीटी के न्यासी मंडल में 16 नवंबर, 2018 के संकल्प संख्या 125/2018-19 के द्वारा निम्नलिखित संकल्प किया:-

- (क) उक्त परियोजना का “तंगहाल परियोजना” के रूप में वर्गीकरण करने के मैसर्ज एवीसीटीपीएल के प्रस्ताव विचार करें और मंत्रालय के 11 जुलाई, 2018 के निदेशों के अनुपालन में इसे तंगहाल परियोजना समझा जाए।
- (ख) “संशोधन, आशोधन या परिवर्तन” के संबद्ध में रियायत करार के अनुच्छेद 21.9 के उपबंधों के अंतर्गत ग्राही मैसर्ज एवीसीटीपीएल के साथ परामर्श करते हुए भंडारण प्रभारों को युक्तियुक्त बनाने का एक उपयुक्त प्रस्ताव प्राधिकरण को भेजा जाए ताकि प्राधिकरण के दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं के अनुसार एआरआर प्राप्त हो सके।
- (ग) प्राधिकरण को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में, भंडारण प्रभारों को युक्तियुक्त बनाने के लिए कार्गो के भंडारण के निशुल्क समय को वर्तमान 5 दिन को बढ़ाकर, जैसा रियायत करार में अनुबद्ध है, 20 दिन कर दिया जाये क्योंकि इस पर ग्राही और रियायत प्राधिकारियों, दोनों ने ही, सहमति जताई है। ग्राही को वीपीटी के माध्यम से प्राधिकरण को विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा जाए जिसमें भंडारण प्रभारों को युक्तियुक्त बनाने के लिए भंडारण अवधि को बढ़ाने के उपयुक्त औचित्य बताए जाएं।
- (घ). मंत्रालय के 11.07.2018 के आदेश के अनुसार “संशोधन, आशोधन या परिवर्तन” के संबद्ध में रियायत करार के अनुच्छेद 21.9 के उपबंधों के अंतर्गत आवश्यक आशोधन किये जाएं।
- (ङ) प्रस्ताव पर एक वर्ष की अवधि के लिए सुविचार किया जाए तत्पश्चात् इसकी समीक्षा की जाए।

3.2. वीपीटी ने वीपीटी बोर्ड के निर्णय की सूचना एवीसीटीपीएल को दी। प्रत्युत्तर में एवीसीटीपीएल ने भंडारण प्रभारों को युक्तियुक्त बनाने के लिए वीपीटी को संबोधित अपने 9.1.2019 के पत्र संख्या एवीसीटीपीएल/स्ट्रैस्ड प्रोजेक्ट/सीई/2018-19/91 के द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। एवीसीटीपीएल ने अनुरोध किया कि निशुल्क भंडार अवधि को 5 से बढ़ाकर 45 दिन किया जाये और तदनुसार उसने भंडारण प्रभारों को युक्तियुक्त बनाने का प्रस्ताव वीपीटी को सौंपा। एवीसीटीपीएल द्वारा अपने 9 जनवरी, 2019 के वीपीटी को संबंधित प्रस्ताव में उठाये गए मुद्दे इस प्रकार हैं:-

- (i) एवीसीटीपीएल ने इस प्राधिकरण के 28 जनवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या टीएएमपी/36/2014-वीपीटी के द्वारा महापत्तनों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण दिशानिर्देशों के अनुपालन में विशाखापट्टणम पत्तन में डीबीएफओटी आधार पर वीपीटी की बर्थ संख्या ईक्यू-1 पर वाष्प कोयले के मशीनीकृत प्रहस्तन से संबंधित 2 जनवरी 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/36/2014-वीपीटी द्वारा अनुमोदित दरमानों की अधिसूचना के आशोधन का प्रस्ताव किया है।
- (ii) इस परियोजना के अपफ्रंट प्रशुल्क इस प्राधिकरण के 2 जनवरी 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/36/29014-वीपीटी द्वारा एवीसीटीपीएल के नाम से अधिसूचित कराये गए थे। मौजूदा दरमानों में 5 दिन की निशुल्क भंडारण अवधि निर्धारित की गई थी जो परियोजना की संकल्पना के सम प्रचलित शर्तों के आधार पर बोली के समय यथा संकल्पित हैं। जबकि, वास्तविक प्रथा में यह पाया गया है कि औसत ठहराव समय 45 से 50 दिन होता है। समग्र प्रहस्तन प्रभारों के % के रूप में भंडारण प्रभार इस प्राधिकरण की 26 जनवरी, 2008 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचना नीतिपरक दिशानिर्देशों में संकल्पित 1% से काफी अधिक हैं।
- (iii) पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) द्वारा 11 जुलाई 2018 के पत्र के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक ऐसा, प्रचालक, जिसने निम्नलिखित मानदंड पूरे किये हों, तंगहाल आस्ति के रूप में घोषित किया जायेगा, जिससे वह भंडारण प्रभारों के युक्तिकरण का पात्र हो जायेगा।
 - (क) परियोजना का उपयोग कम हुआ है जैसा पिछले वित्त वर्षों के दौरान प्रचालक द्वारा वास्तव में बोली दस्तावेजों के एक भाग के रूप में डीपीआर/व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार प्रक्षेपण के 70% से भी कम कार्गो प्रहस्तन हुआ है।

- (ख) परियोजना एसपीवी पिछले दो वित्त वर्षों में लगातार नकद हानि वहन कर रहा है।
- (ग) कि ग्राही द्वारा वहन हानियों से प्रचालन अवधि के दौरान उसकी उच्च नेट-वर्थ में कम से कम 50% का क्षरण हुआ है।
- (iv) एवीसीटीपीएल प्रशुल्क की वसूली से प्रस्तावित एआरआर प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए विभिन्न व्यक्तिक सेवाओं के लिए अधिकतम प्रशुल्क को प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त रूप से इस प्रकार नियत किया जाए कि वह प्राधिकरण दिशानिर्देशों के खंड 3.8.2. के अनुसार एआरआर प्राप्त कर सके।
- (v) वर्तमान स्थिति के अनुसार एवीसीटीपीएल तंगहाल परियोजना के रूप में घोषित किया जाने का पात्र है और इसकी वीपीटी ने अपने 12 दिसंबर, 2018 के पत्र के द्वारा पुष्टि भी की है।
- (vi) अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश के अनुलग्नक III के अनुसार (जो कोयला प्रहस्तन टर्मिनल के लिए है) कुल राजस्व अपेक्षा संविभाजन के मानक इस प्रकार हैं:-

प्रशुल्क वर्ग	आबंटित कुल राजस्व का प्रतिशत
कोयला प्रहस्तन प्रभार	98
भंडारण प्रभार	1
विविध प्रभार	1

- (vii) पता लगाई गई तंगहाल आस्तियों के लिए, एमओएस द्वारा यह सूचित किया गया है कि आवधिक समीक्ष के साथ बर्थ की क्षमता के इष्टतम उपयोग को ध्यान में रखकर स्थानीय स्थितियों के आधार पर निशुल्क अवधि के विस्तार के लिए वीपीटी को आवश्यक प्राधिकार दिया गया है।
- (viii) तदनुसार, एवीसीटीपीएल ने वीपीटी को निशुल्क अवधि (जो रियायत करार के अनुसार अभी 5 दिन है) को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। अनेकों बार चर्चा के बाद, वीपीटी द्वारा निशुल्क भंडारण अवधि को बढ़ाकर 20 दिन करने का निर्णय लिया है। उस समय तक एवीसीटीपीएल उस बैठक का एक हिस्सा थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था। एवीसीटीपीएल ने उस बैठक में भी भाग लिया जहां रियायतकारी प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया था।
- (ix) एवीसीटीपीएल का वर्तमान व्यवसाय यह अपेक्षा करता है कि निशुल्क भंडारण अवधि लगभग 45-50 दिन की हो और कि वीपीटी द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसार 20 दिन की अवधि एवीसीटीपीएल के लिए व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। एवीसीटीपीएल को एक पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि वीपीटी द्वारा एमओएस द्वारा उनके 11.07.2018 के पत्र द्वारा दिये गए दिशानिर्देशों के अनुरूप, निशुल्क भंडारण अवधि (जो अभी 5 दिवस की है) को बढ़ाकर 20 दिन कर दिया गया है (यानी निशुल्क अवधि में 15 दिन की बढ़ोत्तरी)। तथापि, उन्हीं दिशानिर्देशों के अनुसार, वीपीटी रियायतकारी प्राधिकरण के रूप में, निशुल्क भंडारण दिवसों को उस सीमा तक नियत कर सकता है जिससे पत्तन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो जाए और एवीसीटीपीएल ने निवेदन किया है। 20 दिन की निशुल्क अवधि से, एवीसीटीपीएल ऐसा कर सकने में सक्षम नहीं होगा और कि आदेश की वास्तविक भावना को समझते हुए एवीसीटीपीएल ने अनुरोध किया है कि निशुल्क भंडारण दिनों की संख्या को 5 से बढ़ाकर 45 दिन किया जाए।
- (x) एमओएस के दिशानिर्देशों के अनुसार, एवीसीटीपीएल निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:
- (क) कोई भंडारण प्रभार नहीं, और यदि कार्गो निष्पादित करार के अनुसार (यानी 5 दिन) निशुल्क अवधि के भीतर क्लीयर हो जाता है तो वीपीटी को कोई रायल्टी संदेय नहीं होगी।
- (ख) यदि कार्गो निष्पादित करार के अनुसार निशुल्क अवधि की समाप्ति के बाद, परंतु विस्तारित निशुल्क अवधि के भीतर क्लीयर होता है, यद्यपि कोई भंडारण प्रभार नहीं है परंतु ग्राही एआरआर के 1% के समान रायल्टी अदा करेगा, और

(ग) यदि कार्गो विस्तारित निशुल्क अवधि में (45 दिन से इतर) क्लीयर होता है, ग्राही वसूल किये गए वास्तविक भंडारण प्रभारों पर उद्धृत% के समान अथवा विस्तारित अवधि से इतर अवधि के लिए एआरआर के 1% के समान, जो भी अधिक हो, रायल्टी की अदायगी करेगा।

(xi) तदनुसार, एवीसीटीपीएल ने मौजूदा और प्रस्तावित दरों की तुलना निम्नवत् प्रस्तुत की है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	मौजूदा दरमान (यथा लागू वार्षिक सूचकांकन लागू करने के पश्चात् है।)	प्रस्तावित दरमान
1.	बर्थ किराया प्रभार (विदेशगामी पोत)	रु./जीआरटी एच पोत)	0.676	0.676
2.	कार्गो प्रहस्तन प्रभार (विदेशी कार्गो)	रु./ एमटी	203.93	203.93
3.	भंडारण प्रभार (0-5 दिन)	रु./एमटी प्रति दिन	शून्य	शून्य
4.	भंडारण प्रभार (6-10 दिन)	रु./एमटी प्रति दिन	2.06	शून्य
5.	भंडारण प्रभार (11-15 दिन)	रु./एमटी प्रति दिन	4.05	शून्य
6.	भंडारण प्रभार (16-45 दिन)	रु./एमटी प्रति दिन	8.09	शून्य
7.	भंडारण प्रभार 46 ^{वें} दिन से आगे	रु./एमटी प्रति दिन	8.09	8.09
8.	विविध प्रभार (झाड़ू लगाने, धूल दमन और पर्यावरण आदि के प्रभार)	रु./ एमटी	2.08	2.08

(xii) इसके अतिरिक्त, भंडारण प्रभारों की मौजूदा और प्रस्तावित रायल्टी की तुलना निम्नवत् है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	मौजूदा रायल्टी	प्रस्तावित रायल्टी
1.	भंडारण प्रभार (0-5 दिन)	रु./एमटी प्रति दिन	कोई रायल्टी नहीं	कोई रायल्टी नहीं
2.	भंडारण प्रभार (6-10 दिन)	रु./एमटी प्रति दिन	सकल राजस्व पर 40.29%	1% एआरआर
3.	भंडारण प्रभार (11-15 दिन)	रु./एमटी प्रति दिन	सकल राजस्व पर 40.29%	1% एआरआर
4.	भंडारण प्रभार (16-45 दिन)	रु./एमटी प्रति दिन	सकल राजस्व पर 40.29%	1% एआरआर
5.	भंडारण प्रभार 46 ^{वें} दिन से आगे	रु./एमटी प्रति दिन	सकल राजस्व पर 40.29%	वसूल किये गए वास्तविक भंडारण प्रभार के 40.29% के समान रायल्टी अथवा एआरआर का 1% जो भी अधिक हो।

- (xiii) तदनुसार, एवीसीटीपीएल ने वीपीटी को अनुरोध किया कि वीपीटी 45 दिन तक निशुल्क भंडारण दिनों की अनुमति दे और प्राधिकरण से विचार-विमर्श के साथ ऐसे निशुल्क दिनों का आदेश प्राप्त करे।

4.1. तथापि, वीपीटी ने वीपीटी के बोर्ड संकल्प संख्या 125/2018-19 के निर्णय के एवीसीटीपीएल के 9 जनवरी 2019 के प्रस्ताव को संशोधित कर दिया है। मौजूदा भंडारण प्रभार, प्रस्तावित प्रशुल्क और भंडारण प्रभारों के संबंध में रायल्टी की तुलनात्मक स्थिति, वीपीटी द्वारा यथा संशोधित और पत्तन द्वारा प्रस्तावित, नीचे सारणीबद्ध की जाती है:

क्र.सं.	भंडारण दिन	भंडारण प्रभार/एमटी/ दिन		वीपीटी को रायल्टी का % *	
		मौजूदा	संशोधित	मौजूदा दरमान	संशोधित प्रस्ताव
1.	0 से 5 दिन	अपरिवर्तित	अपरिवर्तित	कोई रायल्टी नहीं	कोई रायल्टी नहीं
2.	6 से 10 दिन	2.02 #	अपरिवर्तित	40.29%	एआरआर का 1%
3.	11 से 15 दिन	4.05 #	अपरिवर्तित	40.29%	एआरआर का 1%
4.	16 से 20 दिन	8.09 #	अपरिवर्तित	40.29%	एआरआर का 1%
5.	21 वें दिन से आगे	8.09	8.09	40.29%	वसूल किये गए वास्तविक भंडारण प्रभार के 40.29% के समान रायल्टी अथवा एआरआर का 1% जो भी अधिक हो।

[# वर्ष 2018-19 के लिए सही दर 2.06, 4.13, 8.26 है।

* इस प्राधिकरण को दरमान नियत करने का अधिदेश है। प्राधिकरण के पास रायल्टी संबंधी मामलों का अधिदेश नहीं है जो पत्तन और संबंधित वीओटी प्रचालक के बीच का मामला है।]

4.2. वीपीटी ने बताया है कि निशुल्क अवधि में वृद्धि और भंडार प्रभार को युक्तियुक्त बनाने का संशोधित प्रस्ताव एमओएस के 11.07.2018 के पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी द्वारा संसूचित समिति के सुझावों के अनुरूप है। इसलिए वीपीटी ने भंडारण प्रभारों को युक्तियुक्त बनाने के यथा संकल्पित प्रस्ताव पर सुविचार करने यथाशीघ्र अधिसूचित करने का अनुरोध किया है ताकि ईक्यू-1 बर्थ सुविधा को व्यावहारिक बनाया जा सके और अतिरिक्त मात्रा को आकर्षित किया जा सके जिससे सुविधा की क्षमता के उपयोग में सुधार लाया जा सके। वीपीटी ने आगे और बताया है कि वीपीटी बोर्ड के संकल्प संख्या 125/2018-19 के अनुपालन में यह प्राधिकरण की अधिसूचना के एक वर्ष पश्चात् भंडारण प्रभारों के प्रस्तावित युक्तिकरण की समीक्षा करेगा और प्राधिकरण से प्रस्ताव को जारी रखने या और संशोधन करने जैसा भी मामला होगा, की अधिसूचना के लिए संपर्क करेगा।

5. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, वीपीटी के 12 फरवरी, 2019 के प्रस्ताव की एक प्रति एवीसीटीपीएल और संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों/ उन आवेदकों को जिनसे 4 मई 2010 के अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश पारित करते समय परामर्श किया गया था, उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भेज दी गई। केवल स्टील अथार्टी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सूचित किया है कि विषयक मामले में उन्हें कोई टिप्पणी नहीं देनी है। इसके अतिरिक्त, हमें किसी अन्य प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठन से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

6. संदर्भाधीन मामले में संयुक्त सुनवाई 17 जून 2019 को वीपीटी परिसर में आयोजित की गई। संयुक्त सुनवाई में वीपीटी और एवीसीटीपीएल ने अपने-अपने निवेदन रखे।

7. वीपीटी को जारी 4 मई 2010 के अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश और 2 जनवरी 2015 के प्रशुल्क आदेश में एवीसीटीपीएल के नाम से अधिसूचित दरमानों में निर्धारित भंडारण प्रभार अनुसूची और संबंधित टिप्पणी (i) के उद्धरण नीचे दिये जाते हैं:-

- (i) आदेश संख्या टीएएमपी/54/2009-वीपीटी दिनांक 4 मई, 2010:

***4. भंडारण प्रभार:**

स्टेक यार्ड में 5 दिनों की निशुल्क अवधि से आगे भंडारित कार्गो के लिए भंडारण प्रभार निम्नानुसार होंगे:-

(दर रु. प्रति टन प्रति दिन या उसके अंश में)

क्र.सं.	वस्तु	निशुल्क अवधि के बाद शेष के कार्गो के लिए पहले पांच दिन हेतु दर	शेष कार्गो के लिए 6वें दिन से 10 वें दिन तक हेतु दर	शेष कार्गो के लिए 11 दिन तथा आगे के लिए दर
1.	स्टीम कोल	1.61	3.22	6.44

टिप्पणी:

- (i) पांच निशुल्क दिन प्रदान किये जाएंगे। पोत से कार्गो पूरी तरह उतार लिए जाने वाले दिन के अगले दिन से निशुल्क अवधि की गणना के लिए सीमा शुल्क अधिसूचित छुट्टी और टर्मिनल के गैर कामकाजी दिन शामिल नहीं किए जाएंगे।"
- (ii) आदेश संख्या टीएएमपी/36/2014-वीपीटी दिनांक 2 जनवरी, 2015:

"4. भंडारण प्रभार:**स्टेक यार्ड में 5 दिनों की निशुल्क अवधि से आगे भंडारित कार्गो के लिए भंडारण प्रभार निम्ननुसार होंगे:-**

(दर रु. प्रति टन प्रति दिन या उसके अंश में)

क्र.सं.	वस्तु	निशुल्क अवधि के बाद शेष के कार्गो के लिए पहले पांच दिन हेतु दर	शेष कार्गो के लिए 6वें दिन से 10 वें दिन तक हेतु दर	शेष कार्गो के लिए 11 दिन तथा आगे के लिए दर
1.	स्टीम कोल	1.97	3.95	7.89

टिप्पणी:

- (i) पांच निशुल्क दिन प्रदान किये जाएंगे। पोत से कार्गो पूरी तरह उतार लिए जाने वाले दिन के अगले दिन से निशुल्क अवधि की गणना के लिए सीमा शुल्क अधिसूचित छुट्टी और टर्मिनल के गैर कामकाजी दिन शामिल नहीं किए जाएंगे।"

8.1. एमओएस ने 11 जुलाई 2018 के अपने ई-मेल द्वारा तंगहाल पीपीपी परियोजना संबंधी पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी दिनांक 11 जुलाई 2018 तंगहाल पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित अध्यक्ष आईपीए की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट की प्रति के साथ 2018 जारी किया।

8.2. समिति की सिफारिशों के आधार पर एमओएस वे पीपीपी परियोजनाओं को "तंगहाल परियोजना" के रूप में वर्गीकरण का निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किया:-

- (क) परियोजना का उपयोग कम हुआ है जैसा पिछले वित्त वर्षों के दौरान प्रचालक द्वारा वास्तव में बोली दस्तावेजों के एक भाग के रूप में डीपीआर/व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार प्रक्षेपण के 70% से भी कम कार्गो प्रहस्तन हुआ है।
- (ख) परियोजना एसपीवी पिछले दो वित्त वर्षों में लगातार नकद हानि वहन कर रहा है।
- (ग) कि ग्राही द्वारा वहन हानियों से प्रचालन अवधि के दौरान उसकी उच्च नेट-वर्थ में कम से कम 50% का क्षरण हुआ है।

8.3. एमओएस का 11 जुलाई, 2018 के पत्र का पैरा 6 बताता है कि जब कभी तंगहाल परियोजनाओं में जैसा एमओएस के उक्त पत्र में परिभाषित किया गया है असामान्य भंडारण प्रभार का मुद्दा सामने आयेगा। पत्तन ग्राही के साथ परामर्श करके भंडारण प्रभारों को युक्तियुक्त बनाने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव के साथ रियायत करार के निबंधन और शर्तों के "करार, आशोधन या परिवर्तन" के उपबंधों के अंतर्गत प्राधिकरण को संपर्क करेगा ताकि प्राधिकरण दिशानिर्देश या अधिसूचना के अनुसार एआरआर प्राप्त किया जा सके। प्राधिकरण को ऐसे प्रस्तावों पर गुण-दोष के आधार पर विचार करना ही होगा। समिति ने रियायतकारी प्राधिकरण द्वारा स्थिति की आवधिक समीक्षा करने की भी संस्तुति की है जिससे सृजित सुविधा का इष्टतम उपयोग किया जा सके।

8.4. एमओएस के उक्त पत्र का हवाला देते हुए, वीपीटी ने अब निशुल्क अवधि में वृद्धि और बीओटी प्रचालक एवीसीटीपीएल के नाम से 4 मई 2018 के आदेश द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ईस्ट क्रे-1 पर स्टीम कोयले के प्रहस्तन के लिए अप फ्रंट दरमानों को अधिसूचित करते हुए 2 जनवरी, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/36/2014-वीपीटी में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित भंडारण अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव दायर किया है। वीपीटी ने 16 नवंबर 2018 को आयोजित वीपीटी बोर्ड के संकल्प की प्रति भी प्रस्तुत की है।

9.1. अपने न्यासी मंडल के अनुमोदन के आधार पर निशुल्क अवधि में वृद्धि और भंडारण अनुसूची में संशोधन के वीपीटी के प्रस्ताव पर निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया का अनुपालन किये जाने के बाद ही अधिसूचित किया जा सकता है जिसमें काफी समय लगता है। अतः कार्गो भंडारण की निशुल्क अवधि के लिए वीपीटी के न्यासी मंडल द्वारा दिये गए अनुमोदन को ध्यान में रखते हुए और वीपीटी द्वारा प्रकट की गई अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्रस्ताव की पावती देते समय हमारे 20 फरवरी 2019 के पत्र के द्वारा वीपीटी द्वारा प्रस्तावित दरों को संशोधित करने के पश्चात् (क्योंकि पत्तन ने वर्ष 2018-19 के लिए 2.07% का सूचकांकन कारक नहीं जोड़ा था) वीपीटी के प्रस्ताव को वीजीसीबीपीएल की मौजूदा भंडारण अनुसूची में संशोधन के लिए निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया अपनाये जाने के पश्चात् भारत के राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी होने तक सिद्धांत रूप से अनुमोदन दे दिया गया था जैसा नीचे दिया गया है। बशर्ते एवीसीटीपीएल वीपीटी के न्यासी मंडल के संकल्प संख्या 125/2018-19 द्वारा आयोजित शर्तों का अनुपालन किया जाए।

भंडारण प्रभार:

(रु. में प्रति टन प्रति दिन या उसके भाग पर)

क्र.सं.	भंडारण दिवस	मौजूदा दरमान के अनुसार एवीसीटीपीएल की वर्तमान दर जैसी वीपीटी द्वारा दी गई है।	सही सूचकांकन कारक लागू करने के पश्चात् मौजूदा दर जैसा हमारे 1 अगस्त 2018 के पत्र में बताया गया है।	संशोधित भंडारण प्रभार
1.	0-5 दिन	शून्य	शून्य	शून्य
2.	6-10 दिन	2.02	2.06 #	शून्य
3.	11-15 दिन	4.05	4.13*	शून्य
4.	16-20 दिन	8.09	8.26*	शून्य
5.	21वें दिन से आगे	8.09	8.26*	8.26

[* वीपीटी ने वर्ष 2018-19 के लिए, प्राधिकरण के 1 अगस्त 2018 के पत्र संख्या टीएएमपी/12/2009-विविध के द्वारा समूचित 2.07% सूचकांकन कारक लागू नहीं किया है। अतः संशोधित मौजूदा दर दी गई है। उदाहरण के तौर पर, अंतिम स्लैब के लिए दर $8.09 \times 1.0207 = 8.26$ होनी चाहिए।]

[# हमारे 20 फरवरी 2019 के पत्र में मामूली सी लिपिकीय गलती है जिसमें दर 2.10 रु. निर्धारित की गई थी। जिसे अब स्लैब 6-10 दिन के लिए संशोधित करके 2.06 रु. कर दिया गया है। इसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि प्रस्तावित संशोधित भंडारण प्रभार और दिये गए सिद्धांत रूप में अनुमोदन में 6-10 दिनों के स्लैब के लिए शून्य दर दी गई है।]

9.2. जहां तक वीपीटी के प्रस्ताव का संबंध है जिसमें एवीसीटीपीएल द्वारा संदेय राजस्व हिस्सा भी शामिल है, वीपीटी के ध्यान में यह ला दिया गया है कि वीजीसीबीपीएल द्वारा वीपीटी को संदेय भंडारण प्रभार पर राजस्व का प्रतिशत हिस्सा एमओएस के तंगहाल पीपीपी परियोजनाओं के बारे में जारी 11 जुलाई, 2018 के पत्र संख्या पीडी-13/11/2018-पीपीपी के अनुसार शासी होगा।

10. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्यवाई इस प्राधिकरण के कार्यालयी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए मतों का सार उनको पृथक् रूप से प्रेषित किया जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

11. मामले की प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभर कर सामने आती है:

- (i) विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव तंगहाल पीपीपी परियोजनाओं से निपटने के संबंध में पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) द्वारा सभी महापत्तनों को जारी 11 जुलाई, 2018 के पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी कक्ष के अनुपालन में वीपीटी में प्रचालन कर रहे वीओटी प्रचालक अदानी विजाग कोक टर्मिनल प्रा.लि. (एवीसीटीपीएल) के दरमान में मौजूदा निशुल्क अवधि में वृद्धि और मौजूदा भंडारण अनुसूची में संशोधन चाहता है; जो अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 द्वारा शासित है।
- (ii) जैसा पहले के पैराओं में चर्चा की गई है, इस प्राधिकरण ने 4 मई, 2010 के आदेश संख्या टीएमपी/54/2009-वीपीटी ने अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अंतर्गत पूर्वी क्वे 1 पर डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर स्टीम कोयला प्रहस्तन के यांत्रिक टर्मिनल के अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारित किये थे। वीपीटी ने इस परियोजना के एवीसीटीपीएल को अवार्ड किया। दिशानिर्देशों के उक्त उपबंधों के अनुपालन में 4 मई 2010 के प्रशुल्क आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अधिसूचित अपफ्रंट प्रशुल्क के संचकांकन के पश्चात् दरमानों को हमारे 2 जनवरी, 2015 को हमारे आदेश संख्या टीएमपी/36/2014-वीपीटी के द्वारा एवीसीटीपीएल के नाम से अधिसूचित किया गया।
- (iii) वीपीटी के वर्तमान प्रस्ताव को संसाधन के लिए लिया जाता है क्योंकि इसे तंगहाल पीपीपी परियोजना के संबंध में सभी महापत्तनों न्यासों को 11 जुलाई 2018 के एमओएस के पत्र के अनुपालन में दायर किया गया है।
- (iv) एमओएस ने अपने 11 जुलाई, 2018 के पत्र में महापत्तन न्यासों द्वारा पीपीपी परियोजनाओं को तंगहाल परियोजनाओं के रूप में वर्गीकरण के तीन मानदंड निर्धारित किये हैं जिन पर पैरा 8.2 में चर्चा की गई है इसलिए संक्षिप्तता के कारण इसे दोहराया नहीं जाता। वीपीटी के न्यासी मंडल ने एवीसीटीपीएल द्वारा प्रहस्तित की जा रही परियोजना को तंगहाल परियोजना घोषित किया है। पत्तन ने एमओएस के पत्र में निर्धारित तीन मानदंडों के बारे में, जिन पर वीपीटी के न्यासी मंडल द्वारा एवीसीटीपीएल की परियोजना को तंगहाल परियोजना के रूप में घोषित करने के लिए सुविचार किया है नीचे प्रस्तुत है:-
- (क) जहां तक पहले प्रतिमान का संबंध है, पिछले 2 वर्षों का क्षमता उपयोग, वीपीटी द्वारा यथा प्रस्तुत, 70% से भी कम रहा है, जैसा वीपीटी ने प्रदर्शित किया है, नीचे सारणीबद्ध किया जाता है:-

वर्ष	प्रहस्तित कार्गो (एमएमटी)
2014-15	1.01
2015-16	0.85
2016-17	शून्य
2017-18	शून्य

[पत्तन ने क्षमता उपयोग प्रतिशत में नहीं दिया है। तथापि पत्तन ने यह बताया है कि वीपीटी में परियोजना को इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क के अनुसार 6.41 एमटीपीए की क्षमता के साथ 8.8.2012 को डीबीएफओटी आधार पर एवीसीटीपीएल को अवार्ड किया था पिछले दो वर्षों में एवीसीटीपीएल द्वारा प्रहस्तित यातायात, वीपीटी द्वारा यथासूचित, जैसा ऊपर सारणी में दिखाया गया है, शून्य क्षमता उपयोग है।]

- (ख) जहां तक अन्य दो प्रतिमानों का संबंध है, पत्तन ने एवीसीटीपीएल के लेखापरीक्षकों से चार्टरित लेखाकारों का यह प्रमाणीकृत करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है। पिछले दो वित्तीय वर्षों की एवीसीटीपीएल की नकद हानि और नेट-वर्थ नीचे सारणीबद्ध की जाती है:

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	वि.वर्ष 2016-17	वि. वर्ष 2017-18
	लाभ हानि विवरण के अनुसार निवल हानि	(4,020.51)	(18,528.60)
	जमा - मूल्यह्रास	2,258.21	1,676.81
	जमा - आपवादिक मदें (हानिकरण प्रावधान)	-	15,518.00
1.	कंपनी द्वारा वहन की गई नकद हानि	(1,762.30)	(1,333.79)
2.	कंपनी की नेट-वर्थ	(1855.84)	(20384.44)

उक्त से यह देखा जाता है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 17.62 लाख करोड़ रुपए की नकद हानि हुई और वर्ष 2017-18 में 13.34 करोड़ रु. की। इसके अतिरिक्त एवीसीटीपीएल की नेट-वर्थ वित्तीय वर्ष 2016-17 में (-) 18.56 करोड़ रु. नकारात्मक थी जो वित्त वर्ष 2017-18 में बढ़ कर (-) 203.84 करोड़ रु. हो गई जो 999% है यानी 50% से ज्यादा का क्षरण हुआ है जो परियोजना को तंगहाल परियोजना के रूप में घोषित करने का एक मानदंड निर्धारित है।

- (v) 4 मई, 2010 के आदेश द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान और इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान और एवीसीटीपीएल के नाम से अधिसूचित, में अनुसूची 4 के नीचे टिप्पणी संख्या 1 के रूप में निशुल्क अवधि के लिए निम्नलिखित उपबंध निर्धारित है।

"पांच निशुल्क दिन प्रदान किये जाएंगे। पोत से कार्गो पूरी तरह उतार लिए जाने वाले दिन के अगले दिन से निशुल्क अवधि की गणना के लिए सीमा शुल्क अधिसूचित छुट्टि और टर्मिनल के गैर कामकाजी दिन शामिल नहीं किए जाएंगे।"

पत्तन का निशुल्क अवधि को मौजूदा 5 दिन से बढ़ाकर 20 दिन करने और परिणामस्वरूप मौजूदा अनुसूची में संशोधन करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, इस प्राधिकरण के 4 मई 2010 के आदेश में अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क में भंडारण अनुसूची और 2 जनवरी, 2015 के एवीसीटीपीएल के नाम से अधिसूचित दरमान के अनुसार, वर्ष 2018-19 और अप्रैल, 2019 से चालू वर्ष 2019-20 के लिए स्वतः सूचकांकन लागू करने के पश्चात् मौजूदा लागू दर तथा वीपीटी द्वारा प्रस्तावित दर तथा दर में मामूली से संशोधन के पश्चात् इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित भंडार प्रभारों की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी जा रही है:

(रु./एमटी टन प्रति दिन और प्रति दिन)

क्र.सं.	विवरण	प्रभार प्राधिकरण के 4 मई 2010 के आदेश में अनुमोदित भंडारण प्रभार	सूचकांकन कारक लागू करने के पश्चात् 2 जनवरी, 2015 के एवीसीटीपीएल के नाम से अधिसूचित दरमान के अनुसार अधिसूचित दरमानों में भंडारण प्रभार	सूचकांकन कारक लागू करने के पश्चात् 2018-19 के लिए लागू भंडारण प्रभार	12 फरवरी 2019 के पत्र में वीपीटी द्वारा प्रस्तावित भंडारण प्रभार	मौजूदा अनुमोदित दर पर 1 अप्रैल 2019 से लागू वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक सूचकांकन कारक लागू करके अद्यतन करने के पश्चात् वीपीटी द्वारा प्रस्तावित भंडारण प्रभार
1.	भंडारण प्रभार (0-5 दिन)	शून्य	शून्य	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं

2.	भंडारण प्रभार (6-10 दिन)	1.61	1.97	2.06	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
3.	भंडारण प्रभार (11-15 दिन)	3.22	3.95	4.13	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
4.	भंडारण प्रभार (16-20 दिन)	6.44	7.89	8.26	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
5.	भंडारण प्रभार 21वें दिन से आगे	6.44	7.89	8.26	8.09	8.26 * (20.02.2019 से 31.03.2019 तक) ##
						8.47 # (01.04.2019 से 19.02.2020 तक)

(* वर्ष 2018-19 के भंडारण प्रभार 2017-18 तक वर्ष 2010 के आधार पर 25.67% लागू चक्रवृद्धि सूचकांकन और वर्ष 2018-19 के लिए 2.07% वार्षिक सूचकांकन लागू करने के पश्चात् निकाला गया है। वीपीटी ने वर्ष 2018-19 के लिए 2.07% की वार्षिक वृद्धि लागू नहीं की है।

वर्ष 2019-20 के लिए लागू भंडारण प्रभार इस प्राधिकरण के वर्ष 2019-20 के लिए 29 मार्च, 2019 के पत्र संख्या टीएमपी/12/2009-विविध के द्वारा घोषित 2.56% के वार्षिक सूचकांकन लागू करने के पश्चात् निकाला गया है।)

20.02.2019 सिद्धांत रूप से अनुमोदन के संसूचन की तारीख है।

(vi) एवीसीटीपीएल ने चाहा है कि वीपीटी निशुल्क अवधि को मौजूदा 5 दिन से बढ़ाकर 45 दिन करने पर सुविचार करे क्योंकि एवीसीटीपीएल को मौजूदा व्यापार चाहता है निकासी की समस्या के कारण कि एवीसीटीपीएल उन्हें 40-42 दिन की निशुल्क अवधि दे। एवीसीटीपीएल ने दलील दी है कि वीपीटी द्वारा निशुल्क अवधि को मौजूदा 5 दिन से बढ़ाकर 20 दिन करने का प्रस्ताव एवीसीटीपीएल को अपनी व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

इस संबंध में, पत्तन ने वीपीटी के न्यासी मंडल के मौजूदा 5 दिन से बढ़ाकर 20 दिन करने के अनुमोदन के अनुपालन में निशुल्क अवधि को बढ़ाने के प्रस्ताव को धारित किया है और यह कि न्यासी मंडल का मौजूदा 5 दिन की निशुल्क अवधि को बढ़ाकर 20 दिन करने का अनुमोदन एक वर्ष की अवधि के लिए है और तत्पश्चात् इसकी समीक्षा की जायेगी। पत्तन की राय यह है कि यदि निशुल्क अवधि बढ़ाकर 45 दिन कर दी जाती है तो इससे टर्मिनल की कार्गो की मात्रा और एवीसीटीपीएल न्यूनतम गारंटी आद्योपांत प्राप्त करने के पश्चात् गारंटी प्रभावी होगी। यह नोट करने योग्य है कि 20 दिन की निशुल्क अवधि के साथ संशोधित भंडारण अनुसूची एवीसीटीपीएल द्वारा 20 फरवरी, 2019 से कार्यान्वित कर दी गई है।

इस प्रकार संक्षेप में, वीपीटी का वीपीटी के न्यासी मंडल द्वारा दिये गये अनुमोदन के आधार पर निशुल्क अवधि को मौजूदा 5 दिन से बढ़ाकर 20 दिन करने का प्रस्ताव एक वर्ष की अवधि के लिए है तत्पश्चात् उसकी समीक्षा की जायेगी।

इस बात को मान्य करते हुए कि वीपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव वीपीटी के न्यासी मंडल के अनुमोदन पर आधारित है और तंगहाल परियोजनाओं पर एमओएस के 11 जुलाई, 2018 के पत्र पर आधारित है और कि यह एक वर्ष की अवधि के लिए है और उसके पश्चात् वीपीटी के न्यासी मंडल द्वारा उसकी समीक्षा की जायेगी और यह सृजित सुविधा के उपयोग में सुधार लाने के लिए है, यह प्राधिकरण पत्तन के वर्तमान प्रस्ताव को अनुमोदित करने को प्रवृत्त है। वीपीटी ने प्रस्ताव फरवरी, 2019 में दायर किया था। चूंकि इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अपफ्रंट प्रशुल्क में स्वतः वार्षिक सूचकांकन

29 मार्च, 2019 के पत्र संख्या टीएएमपी/12/2009-विविध के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए 01 अप्रैल 2019 से लागू है, इसलिए 1 अप्रैल 2019 से लागू 2.56% का वार्षिक सूचकांकन कारक लागू करने के पश्चात् अद्यतन भंडारण प्रभार अंतर्विष्ट करने की आवश्यकता है अर्थात् 8.47 रु./टन/दिन या उसका एक भाग (यानी पत्तन द्वारा प्रस्तावित 8.09 रु. X वर्ष 2018-19 के लिए सूचकांकन 2.07% और वर्ष 2019-20 का 2.56% का सूचकांकन) न कि वीपीटी द्वारा प्रस्तावित 8.09 रु./टन/दिन या उसका एक भाग।

- (vii) जैसा पूर्व के पैराओं में चर्चा की गई है, बताए गए कारणों के लिए वीपीटी के 12 फरवरी 2019 के प्रस्ताव में पत्तन द्वारा प्रस्तावित भंडारण प्रभार में वर्ष 2018-19 के लिए करार सूचकांकन कारक से अद्यतन करके हमारे 20 फरवरी 2019 के पत्र के द्वारा सिद्धांत रूप से अनुमोदन दे दिया या था। पत्तन ने यह भी पुष्टि की है कि संशोधित भंडारण प्रभार 20 फरवरी, 2019 से कार्यान्वित कर दिये गए हैं। जैसा पहले बताया गया है कि वीपीटी के न्यासी मंडल ने प्रस्ताव का अनुमोदन एक वर्ष के लिए किया है और तत्पश्चात् उसकी समीक्षा करेगा। ऐसा है, इसलिए संशोधित भंडारण अनुसूची की वैधता को 20 फरवरी 2019 से 19 फरवरी, 2020 तक की एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया जाता है। संशोधित भंडारण अनुसूची स्वतः व्यपगत हो जायेगी और 2 जनवरी 2015 के आदेश में अधिसूचित मूल भंडारण अनुसूची, ग्राही सूचकांकन के साथ, 20 फरवरी 2020 से लागू हो जायेगी जब तक कि उसकी समीक्षा नहीं की जाती और इस प्राधिकरण द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता।
- (viii) वीपीटी के प्रस्ताव में संदेय रायल्टी का भी प्रस्ताव भी किया गया है, जैसी पहले के पैरा में चर्चा की गई है। इस संबंध में, यह बताया जाता है कि इस प्राधिकरण को दरमान निर्धारित का अधिदेश प्राप्त है। इस प्राधिकरण को रायल्टी संबंधी मामलों पर अधिदेश प्राप्त नहीं है जो पत्तन और संबंधित वीओटी प्रचालक के बीच का मामला है। इस प्रकार, जहां तक एवीसीटीपीएल द्वारा वीपीटी को संदेय भंडारण प्रभारों पर राजस्व हिस्से की प्रतिशत कवरेज पर वीपीटी के प्रस्ताव का संबंध है, यह बताया जाता है कि पत्तन पोत परिवहन मंत्रालय के 11 जुलाई, 2018 के पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी कक्ष द्वारा शासित है। यह स्थिति हमारे 20 फरवरी, 2019 के पत्र में पहले ही स्पष्ट कर दी गई है।
- (ix) चूंकि वीपीटी का वर्तमान प्रस्ताव एक वर्ष की अवधि तक के लिए सीमित और है। यह मान्य करते हुए कि एवीसीटीपीएल के नाम से अधिसूचित भंडारण प्रभार और निशुल्क अवधि, वार्षिक वृद्धि के अधीन पूरी परियोजना के लिए है, यह निर्धारित करना उपयुक्त पाया जाता है कि मौजूदा टिप्पणी (i) निशुल्क अवधि में 5 दिन से 20 दिन की वृद्धि के बारे में और वीपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधित भंडारण अनुसूची को अलग रखा जाए कि 2 जनवरी 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/36/2014-वीपीटी में इस प्राधिकरण द्वारा एवीसीटीपीएल के नाम से अनुमोदित मौजूदा दरमानों से छेड़छाड़ की जाए। उक्त आदेश में अधिसूचित दरमानों में अनुसूची 4 के अनुसार भंडारण प्रभार से संबंधित टिप्पणी संख्या (ii) और (iii) को सुगमता के लिए निर्धारित किया जाता है।

12.1. परिणाम में, और ऊपर दिये गए कारणों से तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण 2 जनवरी 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/36/2014-वीपीटी में इस प्राधिकरण द्वारा एवीसीटीपीएल के नाम से अनुमोदित दरमानों में अनुसूची 4 के अनुसार भंडारण प्रभार से संबंधित मौजूदा अनुसूची को निम्नलिखित अनुसूची से प्रतिस्थापित किया जाता है:

(रु. में प्रति टन/प्रति दिन या उसका भाग)

क्र.सं.	भंडारण दिवस	लागू सूचकांकन के पश्चात् वर्ष 2018-19 के लिए लागू भंडारण प्रभार	लागू सूचकांकन के पश्चात् वर्ष 2019-20 के लिए लागू मौजूदा भंडारण प्रभार	20.02.2019 से 31.3.2019 तक संशोधित भंडारण प्रभार	1.4.2019 से 19.02.2020 तक संशोधित भंडारण प्रभार
1.	0-5 दिन	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
2.	6-10 दिन	2.06	2.11	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं

3.	11-15 दिन	4.13	4.23	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
4.	16-20 दिन	8.26	8.47	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
5.	21 वें दिन से आगे	8.26	8.47	8.26	8.47

टिप्पणी:

- (i) 20 निशुल्क दिन प्रदान किये जाएंगे। पोत से कार्गो पूरी तरह उतार लिए जाने वाले दिन के अगले दिन से निशुल्क अवधि की गणना के लिए सीमा शुल्क अधिसूचित छुट्टि और टर्मिनल के गैर कामकाजी दिन शामिल नहीं किए जाएंगे।
- (ii) भंडारण प्रभार प्रदत्त निःशुल्क अवधि के बाद भी कार्गो के ठहरने के लिए टर्मिनल के गैर कामकाजी दिनों और सीमा शुल्क अधिसूचित छुट्टियों समेत सभी दिनों के लिए देय होगा।
- (iii) कार्गो पर भंडारण प्रभार उस अवधि के लिए नहीं जुड़ेगा जिसमें टर्मिनल प्रचालक, उन कार्गो से उपयोगकर्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर कार्गो सुपुर्दगी देने की। पोत लदान करने की स्थिति में न हो जिनके लिए टर्मिनल प्रचालक जिम्मेदार ठहराया जा सके।
- (iv) उक्त भंडारण अनुसूची 19 फरवरी, 2019 तक वैध रहेगी और यह स्वतः व्यपगत हो जायेगी और 2 जनवरी 2015 के आदेश में अधिसूचित मूल भंडारण अनुसूची, ग्राही सूचकांकन के साथ, 20 फरवरी 2020 से लागू हो जायेगा।

12.2. एवीसीटीपीएल को यह भी निदेश दिया जाता है कि वह प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिन के भीतर वीपीटी के माध्यम से प्रहस्तित कार्गो-वार मात्रा सहित वास्तविक निष्पादन रिपोर्ट और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 2 महीने के भीतर, वास्तविक और वित्तीय दोनों ही, का वार्षिक निष्पादन इस प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./182/19]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

Mumbai, the 6th August, 2019

No. TAMP/14/2019-VPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in pursuance of Ministry of Shipping letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 on Stressed PPP Projects, the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) for increase in free period and amendment in the storage schedule approved by this Authority vide Order No.TAMP/36/2014-VPT dated 2 January 2015 notifying Scale of Rates in the name of Adani Vizag Coal Terminal Pvt. Ltd. for mechanised handling of steam coal at East Quay-1 berth at inner harbour on DBFOT basis in VPT as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/14/2019-VPT

Visakhapatnam Port Trust

Applicant

QUORUM

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 24th day of July, 2019)

This case relates to a proposal dated 12 February 2019 received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) for increase in free period and amendment in the storage schedule approved by this Authority vide Order No.TAMP/36/2014-VPT dated 2 January 2015 notifying Scale of Rates in the name of Adani Vizag Coal Terminal Pvt. Ltd. (AVCTPL) for mechanised handling of steam coal at East Quay-1 berth at inner harbour on DBFOT basis at VPT.

2.1. The main points contained in the VPT proposal are summarised below:

- (i) This project was awarded to AVCTPL at VPT on DBFOT basis on 8.8.2012 with a capacity of 6.41 MTPA. The project was completed on 2.9.2014 and operations commenced on 24.10.2014.
- (ii) It has been represented by the AVCTPL that utilisation of the facility is below par on account of different reasons like change in economic conditions leading to decline in imports of Steam Coal, graduation of some of the volumes from Panamax to Cape vessels and high storage charges. The Concessionaire has also stated the following:

“it has become absolutely difficult and impossible to operate the Berth EQ-1 at Visakhapatnam Port and there is also no scope of improvement in the situation”

- (iii) The issues relating to PPP projects in Major Ports has been raised in various meetings held by the Ministry of Shipping. Considering the importance of the issue, Ministry of Shipping constituted a committee under the Chairmanship of Chairman IPA to take a decision. The report submitted by the committee was forwarded by Ministry of Shipping vide file No.PD-13/1/2018-PPP Cell, dated 11-07-2018 to Major Ports and TAMP directing to adopt the procedure contained therein including review of the situation periodically for optimum utilisation of the facility created.
- (iv) The directions of the Ministry were communicated to the AVCTPL for remarks. In response, AVCTPL vide their letter dated 27 August 2018 has furnished relevant data as per the criteria for classification of “Stressed Project” as per the report of the committee. The AVCTPL has also requested to declare AVCTPL as a Stressed Asset and to consider free days of 40 days for Supramax/ Handy Max vessels and free days of 45 days for Panamax vessels against the existing free period for storage of cargo in stockyard of 5 days.

(a) The main points submitted by the AVCTPL in its letter dated 27 August 2018 are as follows:

- (i) AVCTPL could not handle cargo upto its designed capacity due to various reasons as detailed in our various letters represented to VPT from time to time.

The Details of Cargo handled during preceding four years are as below:

Financial Year	Cargo Handled (MMT)	Remarks
2014-15	0.97	Certificate issued by VPT Traffic Department is furnished.
2015-16	0.88	Certificate issued by VPT Traffic Department is furnished.
2016-17	NIL	Certificate issued by VPT Traffic Department is furnished.
2017-18	NIL	To get the Certificate from VPT Traffic Department.

Total Cargo handled during in last four FYs - 1.85 MMT.

- (ii) AVCTPL is running with huge losses since start of its operations. Cash loss incurred by AVCTPL during the preceding two financial years i.e., 2016-17 and 2017-18 duly certified by its statutory auditor is furnished.
- (iii) Abnormally high storage charges are prohibitive in attracting customers at AVCTPL. Competing ports are cheaper options. All competing ports in the vicinity are offering free storage period from 45 to 60 days.
- (iv) Considering the above, the AVCTPL proposed the following free days to VPT for storage of Cargo at its terminal:

S. No.	Vessel Size	Proposed Free days
1	Supramax/ Handy Max	40
2	Panamax	45

In view of the above, AVCTPL has requested VPT to consider their project as a stressed project and forward proposal of free storage days to TAMP as per MOS guidelines.

2.2. In response to our letter dated 20 February 2019, the VPT vide its letter dated 29 March 2019 has stated that the amended storage schedule for AVCTPL approved in principle was implemented with effect from 20 February 2019 and has submitted the following:

- (i) Actual traffic handled by AVCTPL for the year 2014-15 to 2017-18 are given below:

Year	Cargo Handled (MMT)
2014-15	1.01
2015-16	0.85
2016-17	Nil
2017-18	Nil

- (ii) A copy of letter dated 4 January 2019 of AVCTPL forwarding a Certificate of Chartered Accountant from its Auditors certifying the cash losses and net worth of AVCTPL for the preceding two financial years as tabulated below:

(` in lakhs)

Sr. No.	Particulars	FY 2016-17	FY 2017-18
	Net Loss as per Statement of Profit and Loss	(4,020.51)	(18,528.60)
	Add - Depreciation	2,258.21	1,676.81
	Add - Exceptional Items (impairment provision)	-	15,518.00
1.	Cash Loss incurred by the Company	(1,762.30)	(1,333.79)
2.	Net Worth of the Company	(1855.84)	(20384.44)

The above cash loss and net worth exclude impact of waiver of interest on loan taken from its holding Company during these two years.

3.1. The VPT has placed the request of the AVCTPL to the Board of Trustees of the VPT in its meeting held on 16.11.2018 for review and deliberations. After detailed review and deliberations, the Board of Trustees of VPT is of the opinion to consider the proposal of the Concessionaire M/s.AVCTPL for classification of the said project as “Stressed Project” and has resolved the following, subject to the compliance of the concessionaire to cure the events of defaults as per the directions of the Board and subsequent conditional withdrawal of Consultation Notice by this Authority. The Board of Trustees of VPT vide Resolution No.125/2018-19 dated 16 November 2018 has resolved the following:

- Consider the proposal of M/s.AVCTPL for classification of the said project as “Stressed Project” and to treat the project as stressed project in compliance with the directions of Ministry’s order dated 11 July 2018.
- Approach TAMP under the provisions available at Article 21.9 of the Concession Agreement covering “Amendments, Modifications or Alternations” with an appropriate proposal for rationalization of storage charges in consultation with the Concessionaire M/s.AVCTPL so as to achieve the ARR as per the TAMP guidelines/ notifications.
- Fix the free time for storage of cargo from the existing 5 days as stipulated in the Concession Agreement to 20 days as the same is mutually agreed by both Concessionaire and the Concessioneing Authority for rationalization of storages charges in the TAMP proposal and to inform the Concessionaire to submit a detailed proposal to TAMP through VPT duly justifying the reasonableness of increasing the storage period for rationalization of storage charges.
- Carry out necessary modifications as per the provisions available under Article 21.9 of the Concession Agreement covering “Amendments, Modifications or Alternations” as per the order of the Ministry dated 11.07.2018.
- Consider the proposal for a period of one year and to review thereafter.

3.2. The VPT has communicated the decision of the VPT Board to AVCTPL. In response, AVCTPL has submitted a proposal vide their letter No.AVCTPL/Stressed Project/CE/2018-19/91 dated 9.1.2019 addressed to VPT for rationalisation of storage charges. The AVCTPL has requested that the free storage days be increased from 5 to 45 days and accordingly has submitted a proposal to VPT for rationalisation of storage charges. The main points submitted by AVCTPL in its proposal dated 9 January 2019 addressed to the VPT, are summarised below:

- (i) AVCTPL proposes for modification of the notification of Scale of Rates approved vide Order No.TAMP/36/2014-VPT dated 2 January 2015 pertaining to mechanized handling of steam coal at the berth no.EQ-1 of VPT on DBFOT basis at Visakhapatnam Port in pursuance of the guidelines for upfront tariff setting for Public Private Participation (PPP) projects at Major Ports vide this Authority's Notification No.TAMP/36/2014-VPT dated 28 January 2015.
- (ii) The upfront tariff for this project has been notified by this Authority vide Order No.TAMP/36/2014-VPT dated 2 January 2015 in the name of AVCTPL. The current Scale of Rates prescribes a free storage period of 5 days which is as envisaged at the time of bidding based on the conditions prevailing at the time of conceiving the project, whereas in actual practice it has been observed that the average dwell time is around 45 to 50 days. The storage charges worked as a % of overall handling charges are much higher than the envisaged 1% in the policy guidelines notified by this Authority vide notification dated 26 February 2008.
- (iii) As per the guidelines issued by Ministry of Shipping (MOS) vide letter dated 11 July 2018, each such operator who has fulfilled each of the following criteria was to be declared as a Stressed Asset, which would qualify for rationalization of the storage charges.
 - (a) The project is sub-optimally utilized as evidenced by the actual cargo handled by the operator during two preceding financial years being less than 70% of the projection as per DPR/ Feasibility report forming part of the bid document.
 - (b) Project SPV incurring cash loss continuously for two preceding financial years and
 - (c) That the losses incurred by Concessionaire has caused at least 50% erosion of its peak Net Worth during the operation period.
- (iv) AVCTPL has not been able to achieve the proposed ARR through realization of tariff. The tariff cap for different individual services is, therefore, to be set appropriately by TAMP in such a way as to achieve the ARR Clause 3.8.2. of the TAMP guidelines.
- (v) As per the present conditions, AVCTPL qualifies to be declared as a Stressed Project and the same has been confirmed by VPT in its letter dated 12 December 2018.
- (vi) As per the Annexure III of the upfront tariff guidelines (which is relevant for a Coal handling terminal), the norms for apportionment of total revenue requirement is as follows:

Tariff Group	Percentage of Total revenue allocated
Coal Handling Charges	98
Storage Charges	1
Miscellaneous Charges	1

- (vii) For the identified stressed assets, it was informed by the MOS that necessary authority has been granted to the VPT for extending the free period depending on the local conditions with a view to optimize the capacity utilization of the berth with periodical review.
- (viii) Accordingly, AVCTPL had requested VPT to increase the free period (which is currently 5 days as per the Concession Agreement). After having multiple rounds of discussions, it has been decided by VPT to increase the free storage period to 20 days. To that extent AVCTPL was part of the meeting where this decision was made. AVCTPL also participated in the meeting wherein the decision was made by the Concessioning Authority.
- (ix) The current business of AVCTPL requires that AVCTPL to give free storage period of approximately 45-50 days, and the 20 days period decided by VPT would not be sufficient for AVCTPL to be able to improve its viability. AVCTPL have been informed vide letter confirming that the free storage period (which is currently 5 days) has been extended to 20 days (i.e. 15 extended free period) by VPT in pursuance of the authority given by MOS guidelines vide their letter dated 11.07.2018. However, as per the same guidelines VPT, as Concessioning Authority, can fix number of free storage days that

would make for optimal utilization of the port, and AVCTPL submitted that at 20 days free storage, AVCTPL would not be able to do so, and in order to have the true spirit of the order followed, AVCTPL has requested that the free storage days be increased from 5 to 45 days.

- (x) As per the MOS guidelines, AVCTPL will ensure the following:
- No Storage charges and hence no Royalty is payable to VPT if cargo is cleared within the free period as per executed concession agreement (i.e. 5 days).
 - If the cargo is cleared after the expiry of free period as per the executed concession agreement; but, within the extended free period, no storage charges will be there but the concessionaire shall pay Royalty equal to 1% of ARR and
 - If the cargo is cleared after extended free period (i.e. beyond 45 days), concessionaire shall pay Royalty equal to quoted % on actual storage charges recovered or 1% of ARR whichever is higher for the period beyond the extended period.
- (xi) Accordingly, AVCTPL has submitted the current vs proposed rates as follows:

Sl. No.	Particulars	Units	Current Scale of Rates (This is after applying annual indexation as applicable)	Proposed Scale of Rates
1.	Berth Hire Charges (foreign going vessel)	₹/ GRTH	0.676	0.676
2.	Cargo Handling Charges (foreign cargo)	₹/ MT	203.93	203.93
3.	Storage Charges (0-5 days)	₹/ MT per day	NIL	NIL
4.	Storage Charges (6-10 days)	₹/ MT per day	2.06	NIL
5.	Storage Charges (11-15 days)	₹/ MT per day	4.05	NIL
6.	Storage Charges (16-45 days)	₹/ MT per day	8.09	NIL
7.	Storage Charges 46 th day onwards	₹/ MT per day	8.09	8.09
8.	Misc. charges (charges for sweeping, dust suppression and environment, etc.	₹/ MT	2.08	2.08

- (xii) Further, the current vs proposed royalty on storage charges would be as under:

Sl. No.	Particulars	Units	Current Royalty	Proposed Royalty
1.	Storage Charges (0-5 days)	₹/ MT per day	No royalty	No royalty
2.	Storage Charges (6-10 days)	₹/ MT per day	40.29% on Gross revenue	1% ARR
3.	Storage Charges (11-15 days)	₹/ MT per day	40.29% on Gross revenue	1% ARR
4.	Storage Charges (16-45 days)	₹/ MT per day	40.29% on Gross revenue	1% ARR
5.	Storage Charges 46 th day onwards	₹/ MT per day	40.29% on Gross revenue	Royalty equal to 40.29% on actual storage charges recovered or 1% ARR whichever is higher.

- (xiii) Accordingly, AVCTPL has requested VPT to allow for free storage days till 45 days and to obtain orders with such free storage days in consultation with the TAMP.

4.1. However, the VPT has revised the proposal dated 9 January 2019 of AVCTPL considering free period of 20 days in compliance with the decision of VPT Board Resolution No.125/2018-19. The comparative position of the existing storage charge, proposed tariff and the royalty in respect of storage charges, as revised by VPT and proposed by the port is tabulated below:

Sl. No.	Storage days	Storage charge/MT/Day		% Royalty to VPT *	
		Current SOR	Revised proposal	Current Royalty	Proposed proposal
1.	0 to 5 days	No charges	No charges	No Royalty	No Royalty
2.	6 to 10 days	2.02 #	No charges	40.29%	1% of ARR
3.	11 to 15 days	4.05 #	No charges	40.29%	1% of ARR
4.	16 to 20 days	8.09 #	No charges	40.29%	1% of ARR
5.	21 st day onwards	8.09	8.09	40.29%	Royalty equal to 40.29% on actual storage charges or 1% of ARR whichever is higher

[# Correct rate is 2.06, 4.13, 8.26 for the year 2018-19.

* The mandate of this Authority is to fix SOR. TAMP does not have mandate on Royalty matter which is between port and concerned BOT operator.]

4.2. The VPT has stated that the revised proposal for increase in free period and rationalisation of storage charges is in line with the suggestions of the Committee communicated vide MOS letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11.07.2018. The VPT has, therefore, requested to consider the proposal for rationalisation of storage charges as envisaged and notify the same at the earliest to improve the viability of the EQ-1 facility and to attract additional volumes so that the capacity utilisation of the facility can be improved. The VPT has further stated that it shall review the proposed rationalisation in storage charge after one year of notification by TAMP in compliance of VPT Board Resolution No.125/2018-19 and shall approach TAMP for notification for continuation of the proposal or further revision as the case may be.

5. In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal of VPT dated 12 February 2019 was forwarded to the AVCTPL and concerned users/ user organisations/ Applicants who were consulted while passing the upfront tariff Order dated 4 May 2010 seeking their comments. Only Steel Authority for India Limited has informed that they have no comments to offer with regards to the subject matter. Apart from this, we have not received comments from any other users/ user organisations.

6. A joint hearing on this case in reference was held on 17 June 2019 at VPT premises. At the joint hearing, the VPT and AVCTPL have made their submissions.

7. The relevant extracts of storage charges schedule and relevant Note(i) prescribed in the upfront tariff Order 4 May 2010 issued to VPT and in the tariff Order dated 2 January 2015 notifying SOR in the name of AVCTPL are given below:

(i) Order No.TAMP/54/2009-VPT dated 4 May 2010:

“4. STORAGE CHARGES:

The Storage charges for the cargo stored in the stack yard beyond the free period of 5 days shall be as below:

(Rate in Rs. per tonne per day or part thereof)

Sl. No.	Commodity	Rate for first 5 days for the balance cargo remaining after the free period	Rate for 6 th day to 10 th day for the balance cargo	Rate for 11 th onwards for the balance cargo
1.	Steam coal	1.61	3.22	6.44

Note:

- (i) 5 free days shall be allowed. Free period shall commence from the day following the day of complete discharge of vessel cargo. For the purpose of calculation of free period, Custom notified holidays and Terminal's non-working days shall be excluded."
- (ii) Order No.TAMP/36/2014-VPT dated 2 January 2015:

"4. STORAGE CHARGES:

The Storage charges for the cargo stored in the stack yard beyond the free period of 5 days shall be as below:

(Rate in ₹ per tonne per day or part thereof)

Sl. No.	Commodity	Rate for first 5 days for the balance cargo remaining after the free period	Rate for 6 th day to 10 th day for the balance cargo	Rate for 11 th onwards for the balance cargo
1.	Steam coal	1.97	3.95	7.89

Note:

- (i) 5 free days shall be allowed. Free period shall commence from the day following the day of complete discharge of vessel cargo. For the purpose of calculation of free period, Custom notified holidays and Terminal's non-working days shall be excluded."
- 8.1. The MOS vide its e-mail dated 11 July 2018 has issued the letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July, 2018 on stressed PPP project along with a copy of the report of the Committee chaired by Chairman, IPA on the issue pertaining to Stressed PPP projects.

8.2. Based on the recommendation of the Committee, the MOS has prescribed the following criteria for classification of PPP project as "Stressed Project":

- (a) The project is sub-optimally utilised as evidenced by the actual cargo handled by the operator during two preceding Financial years being less than 70% of the projection as per DPR/ Feasibility report forming part of the bid document and
- (b) Project SPV incurring cash loss continuously for two proceeding, financial years and
- (c) That the losses incurred by concessionaire has caused atleast 50% erosion of its peak Net Worth during the operation period.

8.3. Para 6 of the MOS letter dated 11 July 2018 states that whenever issue of abnormal storage charges emerges in stressed projects as defined in the said MOS letter, the Ports may approach TAMP under the provisions of "Agreements, modification or alternations" to the terms and conditions of the concession agreement with an appropriate proposal for rationalization of storage charges in consultation with concessionaires so as to achieve the ARR as per the TAMP guidelines/ notification. TAMP has to consider such proposals on merit. The Committee also recommended review of the situation by the Concessioning Authority periodically for optimum utilization of the facility created.

8.4. Referring to the said letter of MOS, the VPT has now filed the current proposal for increase in free period and amendment in the storage schedule approved by this Authority in Order No.TAMP/36/2014-VPT dated 2 January 2015 notifying the upfront Scale of Rates for mechanised terminal for handling Steam coal at East Quay 1 approved by this Authority vide Order dated 4 May 2010 in the name of BOT operator AVCTPL. The VPT has furnished a copy of resolution of the Board of Trustees of the VPT held on 16 November 2018.

9.1. The proposal of the VPT for increase in free period and amendment in the storage schedule based on approval of its Board of Trustees could have been notified only after following the consultation process prescribed, which would have taken time. Hence, keeping in view the approval accorded by the Board of Trustees of VPT for the increase in free period for storage of cargo and keeping in view the urgency expressed by the VPT, while acknowledging the proposal, in-principle approval was accorded vide our letter dated 20 February 2019 to the proposal of VPT after correction in the rate proposed by VPT (as port has not applied indexation factor of 2.07% for the year 2018-19) for amendment in the existing storage schedule of VGCBPL as given below pending its notification in the Gazette of India after following the consultation process prescribed, subject to AVCTPL complying with the conditions imposed by the Board of Trustees of VPT in the Board Resolution No. 125/2018-19:

Storage Charges:

(in ₹ per tonne per day or part thereof)

Sl. No.	Storage Days	Existing Rate of AVCTPL as per Current SOR as given by VPT	Existing Rate after applying correct indexation factor as per our letter dated 1 August 2018	Amended Storage charges
1.	0-5 days	Nil	Nil	Nil
2.	6-10 days	2.02	2.06 #	Nil
3.	11-15 days	4.05	4.13*	Nil
4.	16-20 days	8.09	8.26*	Nil
5.	21 st day onwards	8.09	8.26*	8.26

[* The VPT has not applied 2.07% indexation factor for the year 2018-19 as communicated by TAMP vide letter No.TAMP/12/2009-Misc. dated 1 August 2018. Hence, corrected existing rate is given. For example, for the last slab the rate should be $8.09 \times 1.0207 = 8.26$]

[# There was minor typographical error in our letter dated 20 February 2019 prescribing rate at ₹ 2.10 which is corrected here as ₹ 2.06 for the slab 6-10 days. This will not have any impact as amended storage charge proposed and in principle approval accorded is nil for the slab 6-10 days.]

9.2. As regards the proposal of the VPT which also included the revenue share payable by the AVCTPL, it was brought to the notice of the VPT that the percentage of Revenue share on the storage charges payable by the VGCBPL to VPT will be governed as per MOS letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 issued on Stressed PPP Projects.

10. The proceedings relating to joint hearing held in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the arguments made by the parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

11. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

- (i) The proposal mooted by the Visakhapatnam Port Trust (VPT) seeks approval of this Authority for increase in existing free period and amendment in the existing Storage schedule in the SOR of the BOT operator, Adani Vizag Coal Terminal Pvt. Ltd. (AVCTPL) operating in the VPT which is governed by the upfront tariff guidelines of 2008, in pursuance of Ministry of Shipping (MOS) letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 issued to all Major Ports to deal with Stressed PPP projects.
- (ii) As already brought out in the earlier paragraphs, this Authority had vide Order No.TAMP/54/2009-VPT dated 4 May 2010 fixed upfront tariff for mechanised terminal for handling Steam coal at East Quay 1 on Design, Built, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis at VPT under the upfront tariff guidelines of 2008.
The VPT has awarded the project to AVCTPL. In compliance of the said provisions of Guidelines, the SOR was notified in the name of AVCTPL vide Order No.TAMP/36/2014-VPT dated 2 January 2015 after indexing the notified upfront tariff approved by this Authority in the tariff Order of 4 May 2010.
- (iii) The current proposal of VPT is taken up for processing because it is filed in pursuance of the MOS letter dated 11 July 2018 to the Major Port Trusts as regards the stressed PPP project.
- (iv) The MOS in its letter dated 11 July 2018 has prescribed the three criteria for classification of PPP project as Stressed Projects by Major Port Trusts which has been brought out in para 8.2. above and hence not reiterated for the sake of brevity. The Board of Trustees of the VPT has declared the project handled by the AVCTPL as Stressed Project. The port has furnished the following as regards the three criteria prescribed in the MOS letter which has been considered by the Board of Trustees of the VPT for declaring the project of AVCTPL as Stressed Project:

- (a) As regards the first parameter, the capacity utilisation for the preceding two years furnished by the VPT being below 70% as exhibited by VPT is tabulated below:

Year	Cargo Handled (MMT)
2014-15	1.01
2015-16	0.85
2016-17	Nil
2017-18	Nil

[The port has not furnished capacity utilisation in terms of percentage. The Port has, however, stated that this project was awarded to AVCTPL at VPT on DBFOT basis on 8.8.2012 with a capacity of 6.41 MTPA as per the upfront tariff approved by this Authority. The traffic handled by the AVCTPL in the preceding two years reported by the VPT as tabulated above is nil i.e. nil capacity utilisation.]

- (b) As regards the other two parameters, the port has furnished the Certificate of Chartered Accountant from the Auditors of AVCTPL certifying the cash losses and net worth of AVCTPL for the preceding two financial years as tabulated below:

(₹ in lakhs)

Sr. No.	Particulars	FY 2016-17	FY 2017-18
	Net Loss as per Statement of Profit and Loss	(4,020.51)	(18,528.60)
	Add - Depreciation	2,258.21	1,676.81
	Add - Exceptional Items (impairment provision)	-	15,518.00
1.	Cash Loss incurred by the Company	(1,762.30)	(1,333.79)
2.	Net Worth of the Company	(1855.84)	(20384.44)

From above, it is seen that there has been cash losses of ₹ 17.62 lakhs crores in the financial year 2016-17 and ₹ 13.34 crores in the year 2017-18. Further, the net worth of the AVCTPL is reported to be negative to the tune of (-) ₹ 18.56 crores in financial year 2016-17 which has increased to (-) ₹ 203.84 crores in financial year 2017-18 which is 999% i.e. more than 50% erosion prescribed as one of the criteria for declaring the project as stressed project.

- (v) The upfront SOR approved by this Authority vide Order dated 4 May 2010 and the SOR approved by this Authority and notified in the name of the AVCTPL prescribes the following provision as regards free period under Schedule 4 Note No.1.

“5 free days shall be allowed. Free period shall commence from the day following the day of complete discharge of vessel cargo. For the purpose of calculation of free period, Custom notified holidays and Terminal’s non-working days shall be excluded.”

The proposal of the port is to increase the free period from existing 5 days to 20 days and consequently amend the existing storage schedule. Accordingly, a comparative position of storage schedule as per the upfront tariff approved by this Authority vide its Order dated 4 May 2010, as per SOR notified in the name of the AVCTPL vide Order dated 2 January 2015, existing applicable rate after applicable automatic indexation for the year 2018-19 and current year 2019-20 from April 2019, and the storage charges proposed by VPT and that approved by this Authority after minor correction in the rate are given below:

(₹ /MT tonne per day or per day)

Sl. No.	Particulars	Storage Charges approved by Authority vide Order dated 4 May 2010	Storage Charges in the SOR notified in the name of AVCTPL vide Order dated 02 January 2015 after applicable indexation factor	Storage Charges applicable for the year 2018-19 after applicable indexation	Proposed Storage Charge by VPT vide its letter dated 12 February 2019	Storage Charges proposed by VPT based on existing rate approved after updating it with applicable annual indexation factor for the year 2019-20 applicable from 1 April 2019
1.	Storage Charges (0-5 days)	Nil	Nil	No Charges	No Charges	No Charges
2.	Storage Charges (6-10 days)	1.61	1.97	2.06	No Charges	No Charges
3.	Storage Charges (11-15 days)	3.22	3.95	4.13	No Charges	No Charges
4.	Storage Charges	6.44	7.89	8.26	No	No Charges

	(16-20 days)				Charges	
5.	Storage Charges 21 st day onwards	6.44	7.89	8.26	8.09	8.26 * (from 20.02.2019 upto 31.03.2019) # #
						8.47 # (from 01.04.2019 till 19.02.2020)

(* The storage charge applicable for the year 2018-19 is arrived after applying applicable compounded indexation of 25.67% over the base year 2010 till 2017-18 and annual indexation of 2.07% for the year 2018-19. The VPT has not applied annual escalation for the year 2018-19 at 2.07%.

The storage charge applicable for the year 2019-20 is arrived after applying applicable annual indexation of 2.56% announced by this Authority vide letter No.TAMP/12/2009-Misc. dated 29 March 2019 for the year 2019-20.)

20.02.2019 is the date of communication of in-principle approval.

- (vi) The AVCTPL has sought VPT to consider to increase free period from existing 5 days to 45 days citing that current business of AVCTPL requires that AVCTPL to give free storage period of approximately 40-42 days due to evacuation problem. The AVCTPL has contended that the proposed increase by the VPT in free period from existing 5 days to 20 days would not be sufficient for AVCTPL to be able to improve its viability.

In this regard, the port has retained its proposal for increase in the free period from existing 5 days to 20 days in compliance with the approval of the Board of Trustees of VPT for increase in free days to 20 days for a period of one year and to review thereafter. The port has viewed that if free period is increased to 45 days, it will impact cargo volume of the terminal and on AVCTPL achieving the guarantee Minimum Guaranteed Throughput. It is noteworthy that the amended storage schedule with 20 days free period has been implemented with effect from 20 February 2019 by AVCTPL.

Thus, in short the proposal of the VPT is to increase the free period from existing 5 days to 20 days as per the approval accorded by the Board of Trustees of the VPT for a period of one year and to review thereafter.

Recognizing that the proposal filed by the VPT is based on the approval of the Board of Trustees of the VPT and is based on the MOS letter dated 11 July 2018 on the Stressed Project and is for a period of one year and to be reviewed thereafter by the Board of Trustees of the VPT and is intended to improve the utilization of the facility created, this Authority is inclined to approve the current proposal of the port. The VPT had filed the proposal in February 2019. Since the automatic annual indexation in the upfront tariff notified by this Authority is applicable for the year 2019-20 from 1 April 2019 as per letter No.TAMP/12/2009-Misc. dated 29 March 2019, the updated storage charge after applying the applicable annual indexation factor of 2.56% from 1 April 2019 as announced by this Authority needs to be incorporated i.e. `8.47/ tonne/ day or part thereof (i.e. 8.09 proposed by port x 2.07% indexation for the year 2018-19 and 2.56 % indexation for the year 2019-20) instead of `8.09/ tonne/ day or part thereof proposed by VPT.

- (vii) As brought out in the preceding paragraph, for the reasons stated, in principle approval was accorded to the proposal of the VPT dated 12 February 2019 after updating amended storage charge proposed by the port with the indexation factor applicable for the year 2018-19 vide our letter dated 20 February 2019. The port has also confirmed that amended storage charge has been implemented from 20 February 2019. As stated earlier, the Board of VPT has accorded approval to the proposal for one year and review thereafter. That being so, validity of the amended storage schedule is approved by this Authority for the period of one year from 20 February 2019 till 19 February 2020. The amended storage schedule would stand lapsed automatically and the original storage schedule as notified vide Order dated 2 January 2015 with applicable indexation would come into effect from 20 February 2020 unless reviewed by the VPT and approved by this Authority.
- (viii) The proposal of VPT also proposes the royalty payable as brought out in an earlier paragraph. In this regard, it is to state that the mandate of this Authority is to fix Scale of Rates. This Authority does not have the mandate on Royalty matter which is between the port and the concerned BOT operator. Thus, as regards the proposal of the VPT covering percentage of revenue share on the storage charges payable by the AVCTPL to VPT, it is stated that the port will be governed by the MOS letter No.PD-

13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018. This position was already brought out in our letter dated 20 February 2019.

- (ix) Since the current proposal of the VPT is for a limited period of one year and recognizing that the storage charge and the free period prescribed in the SOR notified in the name of the AVCTPL is for the entire project subject to annual escalation, it is found appropriate to prescribe the existing note (i) as regards increase in free period from 5 days to 20 days and amended storage schedule proposed by the VPT separately instead of tinkering with the existing Scale of Rates of the AVCTPL approved by this Authority in the Order No.TAMP/36/2014-VPT dated 2 January 2015. Note nos.(ii) and (iii) relating to storage charge as per the schedule 4 in the SOR notified in the said Order are prescribed for ease of application.

12.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority replaces the existing schedule as per the Schedule 4 in Order approved by this Authority vide Order No.TAMP/36/2014-VPT dated 2 January 2015 notifying the SOR in the name of the AVCTPL with the following Schedule:

(in ₹ per tonne per day or part thereof)

Sl. No.	Storage Days	Storage Charges applicable for the year 2018-19 after applicable indexation	Existing Storage Charges applicable for the year 2019-20 after applicable indexation	Amended Storage Charges from 20.02.2019 till 31.3.2019	Amended Storage Charges from 1.4.2019 till 19.02.2020
1.	0-5 days	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges
2.	6-10 days	2.06	2.11	No Charges	No Charges
3.	11-15 days	4.13	4.23	No Charges	No Charges
4.	16-20 days	8.26	8.47	No Charges	No Charges
5.	21 st day onwards	8.26	8.47	8.26	8.47

Notes:

- (i) 20 free days shall be allowed. Free period shall commence from the day following the day of complete discharge of vessel cargo. For the purpose of calculation of free period, Custom notified holidays and Terminal's non-working days shall be excluded.
- (ii) Storage charges shall be payable for all days including Terminal's non-working days and Customs notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days.
- (iii) Storage charges on cargo shall not accrue for the period when the terminal operator is not in a position to deliver/ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to the Terminal operator.
- (iv) The above storage schedule shall be valid till 19 February 2020 and it shall automatically lapse and the original storage schedule as approved in the Order dated 2 January 2015 with appropriate indexation rates shall come into effect from 20 February 2020.

12.2. The AVCTPL is also directed to furnish the quarterly physical performance including the cargo-wise volume handled through VPT within 15 days on the end of each quarter and annual performance, both physical and financial, within 2 months at the end of the financial year to this Authority.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./182/19]